



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378] नई दिल्ली, बृद्धवार, मिलम्बर 7, 1994/भाद्रा 16, 1916

No. 378] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 1994/BHADRA 16, 1916

विन मंत्रालय  
(गणराज्य विभाग)  
(विदेश कर प्रभाग)  
श्रीश्रसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1994  
(आयकर)

सा. का. नि. 681 (ग्र) —चूंकि भारत गणराज्य की मरकार और फासीसी गणराज्य की सरकार के बीच दोहरे कराधान के परिहार तथा आय और पंजी पर करों के संबंध में विनीय अपवंचन की रोकथाम के लिए किए गए संलग्न अभिसमय को दोनों मंत्रियों द्वारा उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 1 के अनुमार उक्त अभिसमय को लागू करने हेतु अपने अपने वानन के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को एक-दूसरे के द्वारा पुरा करने पर एक शाधिशूचना के माध्यम से अगम्त, 1994 के प्रथम दिवस को लागू किया गया है;

2. उम्निए अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90, कमानी (नाभ) अनिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24ए तथा धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44ए द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय मरकार एवं द्वारा निर्देश देती है कि उक्त अभिसमय के सभी उपबन्ध भारत संघ में प्रभावी होंगे।

[फा. नं. 501/16/80-एफ.टी.डी.]  
धी. वी. श्रीनिवासन, मंत्रीकृत सचिव

अनुबंध

आय और पंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की मरकार

और

फ्रांस गणराज्य की मरकार  
के बीच

अभिसमय

भारत गणराज्य की मरकार और फ्रांस गणराज्य की मरकार, आय और पंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक अभिसमय गम्पन करने की इच्छा से नीचे लिखे अनुमार महमत द्वारा प्रदत्त है:

(1)

## अनुच्छेद-1

## व्यक्तिगत कार्यक्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा, जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अधिकारी द्वारा दोनों राज्यों के निवासी हैं।

## अनुच्छेद-2

## सम्मानित कर

1. जो कर इस अभिसमय के विषय है, वे इस प्रकार है :

(क) भारत में:

- (i) आयकर जिसमें उस पर लगाया गया कोई अधिकार भी शामिल है।
- (ii) अतिकर; और
- (iii) धन कर,  
(इन्हें इसके बाद "भारतीय कर" कहा गया है)

(ख) फास में :

- (i) आयकर (लैस्पो भरहलि रिवेन्यू) जिसमें कोई अवधारणा कर, उससे संबंधित पूर्व-प्रदायगी, (प्रिकाम्पटे) अथवा अग्रिम प्रदायगी भी शामिल है;
- (ii) निगम कर (लैस्पों सर नेम सोईटीस) जिसमें कोई अवधारणा कर, उससे संबंधित पूर्व-प्रदायगी (प्रिकाम्पटे) अथवा अग्रिम प्रदायगी भी शामिल है; और
- (iii) धन-कर (लैस्पो डि सालिडरहिं सर ल फरचून)  
(जिसे इसके बाद "फांसीसी कर" कहा गया है)।

2. यह अभिसमय किसी भी समरूप अथवा सारतः इसी तरह के करों पर भी लागू होगा जो दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा नौज्वाद अभिसमय पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख के पश्चात् पैशांशक 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सकाम प्रांतिकारी किन्हीं भी सारभूत परिवर्तनों के संबंध में एक-सरे को सूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों।

## अनुच्छेद-3

## मामान्य परिभाषाएं

1. इस अभिसमय में जब तक कि विषयगत पाठ में अन्यथा अनेकांत न हो:-

- (क) "भारत" शब्द से अभिप्रेत है — भारत का राज्य क्षेत्र और उसमें शामिल राज्य क्षेत्रीय समुद्र और इसके ऊपर का हवाई क्षेत्र तथा कोई अन्य समुद्री क्षेत्र जिसके

आरे में भारत को, भारतीय कानून के अनुसार प्रभु - सत्ता मम्पन्न अधिकार प्राप्त हैं तथा अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार प्राप्त हैं।

(ख) "फाँस" शब्द से अभिप्रेत है—फाँस गणराज्य के यूरोपिय तथा समुद्र पारीय विमानक्षेत्र जिसमें राज्य क्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर का हवाई क्षेत्र तथा अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार वे क्षेत्र शामिल हैं जिसके भीतर समुद्रतल और इसके अवधारणा और उपरिवर्ती जल के प्राकृतिक संसाधनों को खोज करने और उनका उपयोग के प्रयोजन के लिए प्रभुसत्ता मम्पन्न अधिकार हैं।

(ग) "एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों से विषयगत पाठ अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा फाँस अभिप्रेत है;

(घ) "व्यक्ति" शब्द में कोई व्यष्टि कोई कम्पनी और अन्य सत्ता शामिल है जो संबंधित संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के अन्तर्गत एक कम्पनी अथवा निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;

(ङ) "कम्पनी" शब्द में कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के अन्तर्गत एक कम्पनी अथवा निगमित निकाय के रूप में माना जाता है,

(च) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" प्रीर "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" क्रमण: एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम और संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है:

(छ) "सक्षम अधिकारी" पद से अभिप्रेत है—भारत के मामले में, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में केन्द्रीय सरकार अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि, और फाँस के मामले में, बजट प्रभारी मंत्री अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ज) "राष्ट्रिक" शब्द से अभिप्रेत है—किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता प्राप्त कोई व्यक्ति और कोई ऐसा विधिक व्यक्ति, भागीदारी अथवा संघ जिन्हें उस संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों में इस तरह की वैमियन प्राप्त हो;

(झ) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है—किसी ऐसे जलयान अथवा वायुगान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाय उस स्थिति के

जब उक्त जलयान अथवा वायुयान के बल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;

- (अ) भारतीय कर से मंबंधित “वित्तीय वर्ष” पद से अभिप्रेत है “पूष्पवर्ती वर्ष” जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में परिभाषित है और फासीमी आयकर से अभिप्रेत है कलेण्डर वर्ष;
- (ट) “कर” शब्द से अभिप्रेत है—विवरण वाठ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अथवा फासीमी कर।

2. जहाँ तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अभिसमय के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्दावली का जो उसमें परिभाषित नहीं हुई हो, जब तक विवरण वाठ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस संविदाकारी राज्य के करों से मंबंधित कानूनों के अंतर्गत होता, जिन पर वह अभिसमय लागू होता है।

#### अनुच्छेद-४

##### निवासी

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, “कर्ता संविदाकारी राज्य का निवासी” पद से अभिप्रेत है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर, उस राज्य के कानून के अंतर्गत उसके अधिकास, निवास, प्रबंध-स्थान अथवा इस प्रकार की किसी भी अन्य कर्ताओं के कारण वहाँ पर कर लगाया जा सकता है।

2. जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्य का निवासी हो, वहाँ उसकी हैसियत निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी—

(क) वह उस राज्य का निवासी समझा जाएगा जिसमें उसका स्थायी घर हो, यदि उसका दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थायी घर हो तो उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध धनिष्ट हों (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र);

(ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का निवासित नहीं किया जा सकता है जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र हो, अथवा यदि उसका दोनों संविदाकारी राज्यों के किसी भी राज्य में स्थायी घर नहीं हो, तो उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा जिसमें वह नियमित रूप से रह रहा हो;

(ग) यदि दोनों संविदाकारी राज्यों में नियमित रूप से रह रहा हो अथवा वह किसी भी संविदाकारी

राज्य में नियमित रूप से रह नहीं रहा तो तो उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा जिसका वह राष्ट्रिक है;

(घ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा किसी भी संविदाकारी राज्य का राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से इस मसले को सुलझाएंगे।

3. यदि पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी है तो उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा जिसमें उसका प्रभावकारी प्रबंध-स्थान स्थित है।

#### अनुच्छेद-५

##### स्थायी संस्थापन

1. इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ “स्थायी संस्थापन” पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहाँ किसी उद्यम का कारोबार संपूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. “स्थायी संस्थापन” पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :—

- (क) प्रबंध व्यवस्था का कोई स्थान;
- (ख) कोई शाखा;
- (ग) कोई कार्यालय;
- (घ) कोई कारखाना;
- (ङ) कोई कार्यशाला;
- (च) कोई खाल, तेल अथवा गैस या कोई कुआं, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निर्भर्ता का कोई अन्य स्थान;
- (छ) कोई भाष्णागार जिसमें कोई व्यक्ति दूसरों के लिए भण्डारण सुविधाएं महेया करता हो;
- (ज) विश्री केन्द्र के रूप में प्रयुक्त परिसर;
- (झ) कोई संस्थापना अथवा संरचना जिसका इस्तेमाल प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए किया जाता हो, वगते कि ये कार्यकलाप 183 दिन से अधिक दिन के लिए जारी रहें।

3. कोई भवन स्थल अथवा निर्माण, संस्थापना अथवा असेम्बली प्रोजेक्ट के बल उस स्थिति में कोई स्थायी संस्थापन होगा यदि ऐसा भवन स्थल अथवा प्रोजेक्ट छः महीने से अधिक समय तक जारी रहता है।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, “स्थायी संस्थापन” पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :—

- (क) उस उद्यम से संबंधित माल ग्रथवा पण्य वस्तुओं के भण्डारण ग्रथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ मात्र मुविधाओं का इस्तेमाल करना;
- (ख) मात्र भण्डारण ग्रथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उस उद्यम से संबंधित भाल ग्रथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टाक का रख-रखाव करना;
- (ग) मात्र किसी अन्य उद्यम द्वारा संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उस उद्यम से संबंधित माल ग्रथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टाक का रख-रखाव करना;
- (घ) उस उद्यम के लिए माल ग्रथवा पण्य वस्तुओं की मात्र खरीद करने ग्रथवा उसके बारे में सूचना प्रक्रिया करने के लिए व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;
- (ङ) उस उद्यम के लिए मात्र विज्ञापन, सूचना देने, बैंडारिक अनुसंधान ग्रथवा अन्य प्रारम्भिक ग्रथवा महायक किस्म के कार्यकलापों के प्रयोजनार्थ व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;
- (च) उप-पैराग्राफ (क) में (ङ) तक में उल्लिखित कार्यकलापों के संयोजन के लिए मात्र व्यापार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, वशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप व्यापार के निश्चित स्थान के संपूर्ण कार्यकलाप प्रारम्भिक ग्रथवा महायक किस्म के हों।

5. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी जहां पर कोई स्वतंत्र हैसियत के किसी एजेंट, जिस पर पैराग्राफ 6 लागू होता हो, से भिन्न कोई अधिकृत दूसरे संविदाकारी राज्य में कार्य करता हो, उस उद्यम का प्रथमोलिलिखित संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन का होना तभी मना जाएगा—

- (क) यदि, उस उद्यम की तरफ से उस संविदाकारी राज्य में ठेकों को संपन्न करने का अधिकार प्राप्त हो तथा वह आदतन ऐसे ठेके संपन्न करता हो, जब तक कि उसके कार्यकलाप उद्यम के लिए माल ग्रथवा पण्य वस्तुओं की खरीद करने तक ही सीमित न हों; ग्रथवा
- (ख) उसके पास इस तरह का कोई प्राधिकार नहीं हो किन्तु वह प्रथमोलिलिखित संविदाकारी राज्य में ऐसे माल ग्रथवा पण्य वस्तुओं का एक स्टाक आदतन रखता

हो जिसमें से वह नियमित रूप से इस उद्यम की तरफ से माल ग्रथवा पण्य वस्तुओं की डिलीवरी करता हो।

6. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम को किसी दूसरे संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन का होना मात्र इस कारण नहीं माना जाएगा कि वह किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट ग्रथवा किसी स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट की मार्फत उस दूसरे राज्य में व्यापार चलाता है वशर्ते कि ऐसे अधिकृत अपने कारोबार की सम्मान्य प्रतिक्रिया में कार्य करते हों। तथापि, यदि ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप उस उद्यम की ओर से पूर्णतः ग्रथवा लगभग पूर्णतः समर्पित होते हैं, तो उसे इस पैराग्राफ के अर्थ के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत वाला एजेंट नहीं समझा जाएगा, यदि यह दिखाई देता है कि एजेंट और उद्यम के बीच सांदेश शर्तों के तहत नहीं किये गये हैं।

7. इस तथ्य में कि कोई कंपनी जो किसी एक संविदाकारी राज्य की निवासी है किसी ऐसी कंपनी पर नियंत्रण रखता है ग्रथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी हो ग्रथवा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में (चाहे वह किसी स्थायी संस्थापन के भाष्यम से ग्रथवा अन्यथा) कारोबार चलाती हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों में में किसी भी कंपनी को दूसरी कंपनी का स्थायी संस्थापन नहीं माना जा सकता है।

#### अनुच्छेद-6

##### अचल संपत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल संपत्ति (जिसमें कृषि ग्रथवा नानिकी से प्राप्त आय भी शामिल है) पर प्राप्त आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. “अचल” संपत्ति पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसका अर्थ है, जिसमें संबंधित संपत्ति स्थित है। इस पद में किसी भी दशा में ये शामिल होंगे— अचल संपत्ति के अवसाधन के रूप में संपत्ति, ऐसे अधिकार जिन पर भू-संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल संपत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भेंडारण, लोतों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए, ग्रथवा कार्य के अधिकार के प्रतिकल के रूप में परिवर्तनीय ग्रथवा नियन्त्रण अदायगियों के अधिकार। जलयान, नौकाएं तथा वायुयान अचल संपत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध अवसाधन संपत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किशाएं पर देने ग्रथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग में होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल संपत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल संपत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

## अमुच्छेद 7

## कारोबार संबंधी लाभ

1. किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थिति किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि वह उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार चलाता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उन्हें अंश पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारण हो।

2. परिवार 3 के उत्तरांशों के अधीन रहते हुए, जहाँ वोंहों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थिति किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता हो, तो प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे लाभों को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा जो उस उद्यम स्थिति में प्राप्त होने की ओर रही जब वह एक-समान अथवा उसमें सिन्हासन-जुलती परिस्थितियों में एक समान या उनमें भिन्न-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतया स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है। किसी भी दशा में, यदि किसी स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभों की सही रकम का निर्धारण नहीं किया जा सकता है अथवा उसके निर्धारण में असाधारण कठिनाइयां आती हैं तो स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभों का आकलन उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में संविभाजन करने के आधार पर किया जा सकता है बताते कि इसके परिणाम इस अमुच्छेद में अंतर्किट मिडातों के अनुसार हों।

3. (क) किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने समय उन खर्चों की कटौतियों के रूप में अनुमति दी जाएगी जो उस स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोगनार्थ किए गए हों, जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक खर्च भी शामिल होंगे, चाहे वे उस संविदाकारी राज्य में किए गए हों जहाँ वह स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों और उक्त खर्च उस संविदाकारी राज्य के कागदान कानूनों के उपबंधों और उनकी परिसीमाओं के अध्यवधीन हों। बताते कि जहाँ उस संविदाकारी राज्य का कानून जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक खर्चों की रकम पर कोई प्रतिबंध लगाया है, जिसकी अनुमति दी जा सकती है और उस संविदाकारी राज्य और

ओ.ई.सी.ई. सदस्यना वाले तीसरे राज्य के बीच 1-1-1990 के बाद हस्ताक्षरित किसी ऐसे अभिसमय, करार अथवा प्रोतोकोल के द्वारा उस प्रतिबंध में दी दी जाती है अथवा उसे रद्द कर दिया जाता है, जो उस अभिसमय के प्रवृत्त होने के बाद प्रवृत्त हो, तो उसे संविदाकारी राज्य के प्राधिकारी उक्त अभिसमय, करार अथवा प्रोतोकोल के प्रवृत्त होने के तुरन्त बाद उस तीसरे राज्य के साथ किए गए अभिसमय, करार अथवा प्रोतोकोल में दिये गये संगत पैराग्राफ की शर्तों को दूसरे संविदाकारी राज्य के सभी प्राधिकारी को अधिसूचित करेंगा, बताते कि इससे संविदाकारी राज्य के सभी प्राधिकारी ने इसके लिए अनुरोध किया हो तो तो इस अभिसमय के तहत उक्त पैराग्राफ के उपबंध उस दिन से लाग होंगे जिस दिन वह प्रवृत्त होगा।

(ख) नथापि, रायलिट्यों, फीसों के रूप में उद्यम के मुख्य कार्यालय अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को स्थायी संस्थापन द्वारा प्रदत्त (वास्तविक खर्चों की प्रतिरूपि में भिन्न) रकमों, यदि कोई हों, के संबंध में पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारी के इस्तेमाल के बदले में, अथवा विशिष्ट सेवा-निष्पादन अथवा प्रबंध व्यवस्था के सिलिले में कमीणत अथवा बैकिंग उद्यम के मामले को छोड़कर स्थायी संस्थापन को उदार दिये गए धन पर व्याज के रूप में इसी प्रकार को अन्य अदायगी के संबंध में ऐसी किसी कटौती को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में रायलिट्यों, फीसों अथवा पेटेंटों अथवा अन्य अधिकारों के इस्तेमाल के बदले में, अथवा विशिष्ट सेवा-निष्पादन या प्रबंध व्यवस्था के सिलिले में कमीणत के रूप में, अथवा बैकिंग उद्यम के मामले के अन्यता उस उद्यम के मुख्य कार्यालय या उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालयों को दिये गये व्याज के रूप में कोई इसी प्रकार की अन्य अदायगी के रूप में उद्यम के मुख्य कार्यालय अथवा किसी कार्यालय में से किसी अन्य को उस स्थायी संस्थापन द्वारा प्रभारित राशियों (वास्तविक खर्चों की प्रतिरूपि में भिन्न) का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा।

4. कोई भी ऐसा लाभ मात्र हम कारण में किसी स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उस उद्यम के लिए माल अथवा पाण्य वस्तुएं खरीदी गई हैं।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोगनार्थ, स्थायी संस्थापन के कारण उन्नप्त हुए समझे जाने वाले लाभों का तब तक विषेन्विष्व उसी पद्धति से निर्धारण किया जाता रहेगा जब तक कि उसके विपरीत उचित तथा पर्याप्त कारण नहीं हों।

6. जहां पर लाभों में शाय की ऐसी मर्दे शामिल हैं जिनका इस अधिसमय के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां पर उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

#### अनुच्छेद-8

##### वायु परिवहन

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा प्रत्यार्पित यातायात में वायुयान के परिचालन से प्राप्त लाभों पर उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. दैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन ऐजेन्सी में भागीदारीना से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोगनार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में वायुयानों के परिचालन से संबंधित निधियों पर प्राप्त व्याज को ऐसे वायुयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों के रूप में समझा जाएगा और अनुच्छेद 12 के उपबंध ऐसे व्याज के संबंध में लागू होंगे।

4. "वायुयान के परिचालन" पद से अभिप्रेत है — वायुयान के मालिकों अथवा पटुशार्ग अथवा चार्टरें द्वारा यात्रियों डाक, पशुओं अथवा माल को हवाई भार्ग से लाने ले जाने का कारोबार जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री, वायुयान का प्रासारणीक पट्टा और ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप भी शामिल हैं।

#### अनुच्छेद-9

##### नौबहन

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा प्रत्यार्पित यातायात में जलयानों के परिचालन से प्राप्त लाभों पर उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होने हुए भी, ऐसे लाभों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जहां से वे प्राप्त हुए हों वहां कि इस प्रकार प्रभारित कर वीर्य उक्त संविदाकारी राज्य के आन्तरिक कानून के नहीं अन्यथा लगाए गए कर की सामा निम्नलिखित में अधिक नहीं हो :—

(क) इस अधिसमय के लागू होने के बाद प्रथम पान विस्तृत वर्णन, 50 प्रतिशत; और

(ख) पूर्ववर्ती पांच विस्तृत वर्षों के दौरान, 25 प्रतिशत।

इसके बाद, केवल पैराग्राफ 1 के उपबंध ही लागू होंगे।

3. पैग 1 और 2 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा जलयानों के संचालन में लाभी हुई किसी अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन ऐजेन्सी से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोगनार्थ अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलयानों के परिचालन से संबंधित निधियों पर प्राप्त व्याज जो ऐसे पोतों के परिचालन में उद्भूत लाभों के रूप में समझा जाएगा और अनुच्छेद 12 के उपबंध ऐसे व्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

#### अनुच्छेद - 10

##### सहबद उद्यम

जहां :

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम प्रबंध व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूँजी के सिलसिले में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

(ख) वही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य किसी उद्यम की प्रबंध व्यवस्था, नियंत्रण अथवा पूँजी के सिलसिले में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

दोनों ही अवस्थाओं में, दोनों उद्यम के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसा रखी अथवा लगाई जाती हों जो उन शर्तों से भिन्न हों जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की वजा में दोनों उद्यमों में से किसी एक उद्यम प्राप्त हुआ होता परन्तु उन शर्तों के कारण वह इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ हो, उस उद्यम के L<sup>oos</sup> से सम्मिलित किया जा सकेगा और तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

#### अनुच्छेद-11

##### लाभांश

1. किसी एक संविदाकारी राज्य की निवासी कंपनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे।

2. तथापि, इस प्रकार के लाभांश उम संविदाकारी राज्य में भी कराधेय होंगे, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुमार वहां की निवासी है लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का हितभीषी स्वामी है, तो इस प्रकार के प्रभारित कर की रकम उक्त

लाभांशों की सकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी।

यह पैराग्राफ उस कंपनी के उन लाभों में संबंधित कराधान को प्रसवित नहीं करेगा जिस में लाभांशों का भुगतान किया जाता है।

3. (क) भारत का ऐसा कोई निवासी, जो किसी ऐसी कंपनी से लाभांश प्राप्त करता है जो फांस का निवासी है और जो यदि फांस के किसी निवासी द्वारा प्राप्त किया गया होता, तो ऐसा निवासी किसी पर ऐडिट (एवायर फिस्कल) के लिए पात्र होता, फांसीसी राजकोष से ऐसे कर ऐडिट (एवायर फिस्कल) के बगबगर राशि की अदायगी के लिए हकदार होगा बश्ते कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार कर की कटौती की गई हो।

(ख) इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (क) के उपबंध भारत के केवल उम्म निवासी पर लागू होंगे जो

- (i) कोई व्यष्टि है ; अथवा
- (ii) कोई ऐसी कंपनी है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में लाभांश अदा करने वाली फांसीसी कंपनी की पूँजी के 10 प्रतिशत में कम पूँजी धारण करती है।

(ग) इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (क) के उपबंध उम्म स्थिति में लागू नहीं होंगे जब फांसीसी राजकोष से उस अदायगी का प्राप्तकर्ता, जिसके लिए इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (क) में उपबंध किया गया है, पर अदायगी के संबंध में भारतीय कर नहीं लगाया जाना हो।

(घ) फांसीसी राजकोष से प्राप्त अदायगियों को, जिनके संबंध में इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (क) के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है, इस अभिसमय के प्रयोजन के लिए लाभांश के रूप में समझा जाएगा।

4. जब किसी ऐसी कंपनी द्वारा जोकि फांस की निवासी है, भारत के किसी ऐसे निवासी को अदा किए गए लाभांशों के संबंध में, जोकि ऐसे लाभांशों से संबंधित इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित फांसीसी राजकोष से भुगतान के लिए हकदार नहीं है, पूर्व-अदायगी (प्रिकाम्प्ट) पर कर लगाया जाता है तो ऐसा निवासी उस पूर्व-अदायगी की वापसी का हकदार होगा, बश्ते कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के अनुसार वापस की गई रकम के संबंध में अवधारण कर की कटौती कर दी गई हो।

5. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “लाभांश” शब्द का अभिप्राय है—येरों अथवा अन्य अधिकारों में, जो ऐसे झूण

दावे नहीं हों, जो लाभ में शामिल होने हैं, प्राप्त आय तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय जिस पर उसी प्रकार की कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस मंविदाकारी राज्य के कानूनों द्वारा येरों में प्राप्त आय के मामले में लागू होती है जिसमें वितरण करने वाली कंपनी निवासी है और कोई अन्य भद्र को (अनुच्छेद 12 के उपबंधों के भीतर आने वाले व्याज से भिन्न) उस कानून के अन्तर्गत लाभांश अथवा वितरण के रूप में समझा जाएगा।

6. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उम्म स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांशों का हितभोगी स्वामी, जो किसी एक मंविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवासी है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं सम्पन्न करता है और जिस सम्बन्ध के संबंध में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वे इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध हैं। ऐसे मामलों में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

7. जहां कोई कंपनी, जो किसी मंविदाकारी राज्य की निवासी है दूसरे मंविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, ऐसे मामले में उस कंपनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर जहां तक ऐसे लाभांशों को छोड़कर, जो दूसरे मंविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए हों अथवा जहां तक कि ऐसी सम्पत्ति के बारे में लाभांशों की अदायगी की गई हो, जो उस दूसरे मंविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है, उस दूसरे मंविदाकारी राज्य में न तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही कंपनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभकर की किसी का कोई कर लगाया जाएगा भले ही अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः उस दूसरे मंविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

## अनुच्छेद-12

### व्याज

1. किसी मंविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले लधा दूसरे मंविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले व्याज पर उस दूसरे मंविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

2. तथापि, इस प्रकार के व्याज पर उस मंविदाकारी राज्य में भी जहां वह उद्भूत होता है और उस मंविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता व्याज का हितभोगी स्वामी है तो इस प्रकार प्रभाग्नि कर की राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी :

(क) किसी भैंक अथवा वास्तविक रूप से बैंकिंग अथवा वित्तपोषण का कारोबार करने वाले अन्य वित्तीय मन्त्यान

द्वारा अथवा किसी ऐसे उद्यम द्वारा जिसके पास प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ब्याज अदा करने वाली कम्पनी की पूँजी का कम से कम 10 प्रतिशत भाग हो, दिए गए अथवा गारंटीशुदा ऋणों पर ब्याज की सकल राशि का 10 प्रतिशत;

(ब) सभी अन्य मामलों में ब्याज की सकल राशि का 15 प्रतिशत।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होने हुए भी :

(क) किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत ब्याज को उस संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी वहाँ कि यह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो और लाभप्रद रूप से धारित किया गया हो :

- (i) इसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसके किसी राजनीतीक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण; अथवा
- (ii) भारत के मामले में “भारतीय रिजर्व बैंक” और फांस के मामले में “बैंक ऑफ फांस”; अथवा
- (iii) कोई अन्य संस्था जिसके बारे में संविदाकारी राज्यों के मध्यम प्राधिकारी समय-समय पर महसूत हों।

(ख) किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत ब्याज को उस संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी यदि यह इसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा लाभप्रद रूप से धारित किया गया हो और निम्नलिखित द्वारा दिए गए अथवा अनुमोदित किए गए ऋणों अथवा कोई के मध्यम से प्राप्त हुआ हो :

- (i) फांस के मामले में, वि बैंक फैक्टरी डू कामर्स एक्स-ट्रेनिंग अथवा दि कम्पनी फैक्टरी एवं स्टोरिंग (सी. ओ.ए. ए. ए. ई.) ;
- (ii) भारत के मामले में, भारतीय नियन्त्रित्रायात बैंक;
- (iii) अन्य संविदाकारी राज्य की कोई संस्था जो विदेशी व्यापार की सार्वजनिक वित्तपोषण प्रभारी मन्त्र्या है।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्ति “ब्याज” शब्द में अभिप्रेत है—प्रत्येक प्रकार के ऋण-दाताओं से प्राप्त आय, चाहे वे अंधक द्वारा प्रतिभूत हों या नहीं हों, चाहे ऋण-दाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार रखते हों, या नहीं रखते हों, और खास तौर पर, सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से प्राप्त आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से संबंधित प्रीमियम और पृग्स्कार भी शामिल हैं। दोस्रे में की गयी अदायगी के लिये लगाये गये जुमनों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये ब्याज के रूप में नहीं समझा जायेगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभोगी स्वामी, जो किसी संविदा

कारी राज्य का निवासी है, इसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कागेबार चलाना है अथवा उस इसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ स्थित किसी निश्चित स्थान में घृतन्त्र वैयक्तिक सेवाये सम्पन्न करता है और जिस ऋणदाते के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान में प्रभावी रूप से संबंधित हो। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा 15 के उपबंध अवास्थित लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज उस स्थिति में उद्भूत हुआ समझा जायेगा, जब ब्याज प्रदा करने वाला सबंधित वह संविदाकारी राज्य, उस संविदाकारी राज्य का कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो। किन्तु जहाँ ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान है जिसके मध्यम से वह अहं उद्भूत हुआ है, जिस पर ब्याज की अवायाई की गई हो, और इस प्रकार का ब्याज ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा बहन किया जाता है तो इस प्रकार का ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जायगा, जिसमें वह स्थाई संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहाँ ब्याज अदाकर्ता नथा हितभोगी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋणदाते को ध्यास में रखते हुए, जिसके लिये उस ब्याज की रकम प्रदा की गई है, उस रकम में बड़ा जाते हैं जिसके लिये इस प्रकार के संबंधों के नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभोगी स्वामी के बीच महसूत हो गई होती वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध के बल अंतिम वर्णित राशि पर ही लागू होगे। ऐसे मामले में अदायगियों के अतिरिक्त भाग पर इस अभियम्य के अन्य उपबंधों का का सम्पर्क ध्यान रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जायेगा।

### अनुच्छेद-13

तकनीकी मेवाओं के लिये रायलिटियाँ और फीसों और उपस्कर्ता के उपयोग के लिये भगतान

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और इसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की जाने वाली रायलिटियाँ तथा तकनीकी मेवाओं के लिये रायलिटियाँ, फीसों और उपस्कर्ता के उपयोग के लिये भगतान पर उस इसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, ऐसी रायलिटियाँ, फीसों तथा भगतानों पर उस संविदाकारी राज्य में भी जिसमें उद्भूत होती हैं तथा उसी संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार, कर लगाया जा सकेगा, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता उन शेषियों की आय का हित

भोगी स्वामी है तो इस प्रकार लगाये गये कर की राशि ऐसी रायलिट्यों, फीसों और आदायगियों की सकल राशि के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “रायलिट्या” शब्द से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों जिनमें चलचित्र फ़िल्में अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिये फ़िल्में तथा टेपें भी शामिल हैं, कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा माउल, प्लान, गुण्ठ मामला अथवा प्रक्रिया अथवा औद्योगिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव में संबंधित जानकारी के लिये प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के लिये प्राप्त किसी प्रकार की अदायगी अभिषेत है।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “तकनीकी सेवाओं के के लिये फीस” पद से अभिषेत है किसी प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्शदात्री स्वरूप की सेवाओं के प्रतिफल में अनुच्छेद 15 में उल्लिखित स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के लिए अदायगियां करने वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी को की जाने वाली अदायगियों से भिन्न किस्म की अदायगी।

5. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “उपस्करों के उपयोग के लिए भुगतान” पद से अभिषेत है औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपस्करों के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रयोजनार्थ किसी प्रतिफल के रूप में प्राप्त किसी भी किस्म की अदायगी।

6. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि तकनीकी सेवाओं के लिए रायलिट्यों, फीसों अथवा उपस्करों के उपयोग के लिए भुगतान का हितभोगी स्वामी, एक संविदाकारी राज्य के निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए रायलिट्यों, फीसों अथवा उपस्करों के उपयोग के लिए अदायगियां उद्भूत होती हों, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पन्न करता हो, तथा तकनीकी सेवाओं के लिए रायलिट्यों, फीसों अथवा उपस्करों के लिए भुगतान ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित हों। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

7. रायलिट्यों, तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों अथवा उपस्करों के उपयोग के लिए भुगतान एक संविदाकारी राज्य में उप स्थिति में उद्भूत हुए माने जाएंगे जब आदाकर्ता स्थयं वह संविदाकारी राज्य, कोई गाझनीतिक उप-प्रभाग कोई स्थानीय प्रधिकरण हो अथवा उप संविदाकारी राज्य का निवासी हो। तथापि, जहां रायलिट्यों, तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों अथवा उपस्करों के उपयोग के लिए भुगतान करने वाले व्यक्ति का, वह किसी एक संविदाकारी राज्य

का निवासी है अथवा नहीं है, उस संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान, जिसके संबंध में संविदा निष्पन्न किया गया था और जिसके अंतर्गत रायलिट्यों, तकनीकी सेवाओं के लिए फीसों अथवा उपस्करों के उपयोग के लिए भुगतान और ऐसी रायलिट्यों अथवा उपस्करों के लिए भुगतान ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा बहन किये जाते हैं तो ऐसी रायलिट्यों, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अथवा उपस्करों के उपयोग के लिए किया जाने वाला भुगतान, उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

8. जहां अदाकर्ता और हितभोगी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायलिट्यों की रकम, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, अथवा उपस्करों के उपयोग के लिए भुगतान की रकम, रायलिट्यों, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अथवा उपस्करों के उपयोग के लिए किए गए भुगतान को ध्यान में रखते हुए, उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार का संबंध नहीं होते को दगा में अदाकर्ता और हितभोगी स्वामी सहमत हो गये होते, वहां पर इस अनुच्छेद के उपबंध के बाहर अन्तिम वर्णा रकम पर हो जाते हुए। ऐसे मामले में, अदाकर्ता को गई रकम इस प्रधिकरण के अन्य उपबंधों पर यथोचित ध्यान देने हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर-योग्य होगी।

#### अनुच्छेद-14

##### पूँजीगत अभिलाभ

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अबल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त किये जाने वाले अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. ऐसी चल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त हुए अभिलाभों पर, जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी स्थायी संस्थापन की ध्यापार्टिक सम्पत्ति के भाग के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है अथवा जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध किसी निश्चित स्थान से संबंधित चल सम्पत्ति हो, जिसमें ऐसे किसी स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा सम्पूर्ण उद्यम के माध्य) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तरण से प्राप्त होने वाले प्रभिताभि भी शामिल हैं, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जल-यात्रों अथवा वायुयात्रों अथवा ऐसे जलयात्रों अथवा वायुयात्रों के संचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त

अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जाएगा, जिसमें अन्तरणकर्ता कोई निवासी है।

4. किसी ऐसी कंपनी के पूँजीगत स्टाक के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर, जिसकी सम्पत्ति में अत्यधिकतः अथवा अप्रत्यक्षतः मुद्य रूप से अचल सम्पत्ति शामिल हो और जो किसी संविदाकारी राज्य में स्थित हो, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा। इस उपबंध के प्रयोजनों के लिए ऐसी कंपनी के औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक प्रचालनों से संबंधित अचल सम्पत्ति को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

5. पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयर, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कंपनी में कम से कम 10 प्रतिशत शेयरों की भागीदारी को निरूपित करते हैं, के अन्तरण से प्राप्त अनुलाभों पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा।

6. पैराग्राफ 1, 2, 4 और 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी है।

#### अनुच्छेद - 15

#### स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं

1. किसी व्यष्टि द्वारा अथवा व्यष्टियों की किसी भागीदारिता द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी हैं, व्यावसायिक सेवाओं अथवा इसी स्वरूप के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों के निष्पादन से प्राप्त आय पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा सिवाय निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जाएगा :

(क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक नियमित स्थान निर्धारित रूप से उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि अथवा अवधियां उस दूसरे राज्य के संगत "वित्तीय वर्ष" में कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक हों, तो उस मामले में, उक्त आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में निष्पादित उसके कार्यकलापों से प्राप्त होती हो।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षणिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलापों

के साथ-साथ चिकित्सकों, शास्त्र-चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दंत-चिकित्सकों और लेखापालों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं।

#### अनुच्छेद - 16

#### पराश्रित व्यक्तिगत सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 18, 19, 20, 21 और 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो। यदि इस प्रकार का नियोजन किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो वहां से प्राप्त होता है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोलिंगित संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता संगत "वित्तीय वर्ष" के दौरान कुल मिलाकर 183 दिन से अनधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए उस दूसरे संविदाकारी राज्य में मौजूद रहा हो;

(ख) पारिश्रमिक किसी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अर्पण किया जाता है, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है; और

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थान पर अथवा किसी निश्चित स्थान से वहन नहीं किया गया हो, को नियोजक के दूसरे संविदाकारी राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में परिचालित किसी जलयात्रा अथवा वायुयात्रा पर सवार होकर किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर के बाहर उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

#### अनुच्छेद-17

#### निदेशकों की फीस

किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, किसी कंपनी के निदेशक मण्डल के एक सदस्य की हैसियत से, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की एक निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस और अन्य समरूप अदायगियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

## अनुच्छेद-18

मनोरंजनकर्ताओं और एथलीटों द्वारा अर्जित आय

1. अनुच्छेद 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी, संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के द्वारा मनोरंजनकर्ता के रूप में जैसे थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार अथवा किसी संगीतकार अथवा किसी एथलीट के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में इस प्रकार सम्पन्न किए गए अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों में प्राप्त आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

2. जहाँ किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी एथलीट द्वारा अपनी हैसियत से किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों से उद्भूत आय स्वयं उस मनोरंजनकर्ता अथवा एथलीट को प्रोद्भूत न होकर किसी अन्य व्यक्ति को होती है, तो उस आय पर अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा एथलीट के कार्यकलाप निष्पादित हुए हों।

3. पैरा 1 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी एथलीट, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हों, द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में निष्पन्न अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त आय पर प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में केवल उस दशा में कर लगेगा यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उन कार्यकलापों पर व्यय पूर्ण अथवा पर्याप्त रूप से प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों द्वारा वहन किया गया हो, जिसमें उस राज्य का राजनैतिक उप प्रभाग अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं।

4. पैरा 2 और अनुच्छेद 7, 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी, जहाँ किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी एथलीट द्वारा अपनी हैसियत के किसी संविदाकारी राज्य में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के उद्भूत आय स्वयं उस मनोरंजनकर्ता अथवा एथलीट को प्रोद्भूत न होकर किसी अन्य व्यक्ति को होती है, तो उस आर पर अन्य संविदाकारी राज्य में कर केवल उस स्थिति में लगेगा यदि उस अन्य व्यक्ति का व्यय पूर्ण अथवा पर्याप्त रूप से उस दूसरे संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों से किया गया हो, जिसमें उस राज्य का राजनैतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण शामिल है।

## अनुच्छेद-19

सरकारी सेवा के किए परिश्रमिक और पेंशन

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अर्थवा उसके किसी राजनैतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अर्थवा उस संविदाकारी राज्य की सार्वजनिक निधियों में से किसी व्यष्टि को उस संविदाकारी राज्य अर्थवा उसके किसी उप प्रभाग अथवा किसी प्राधिकरण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही लगेगा।

(ब) तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर केवल उस स्थिति में लग सकेगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं और वह व्यष्टि उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य का राष्ट्रिक है और जो सेवाएं सम्पन्न करने के प्रयोगजनार्थ उस राज्य का राष्ट्रिक नहीं बना।

2. किसी संविदाकारी राज्य अर्थवा उसके किसी राजनैतिक उप प्रभाग अर्थवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अर्थवा उन के द्वारा सृजित निधियों में से किसी व्यष्टि को उस राज्य अर्थवा उसके किसी उप प्रभाग अर्थवा प्राधिकरण के लिए सम्पन्न की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई किसी पेंशन पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लग सकेगा।

3. अनुच्छेद 16, 17 और 20 के उपबंध एक संविदाकारी राज्य, उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अर्थवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी कारोबार के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए पारिश्रमिक और पेंशनों पर लागू होंगे।

## अनुच्छेद-20

गैर सरकारी पेंशन और वार्षिकियाँ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के अंदर उपलब्ध स्रोतों से अनुच्छेद 19 में उल्लिखित पेंशन से भिन्न कोई अन्य पेंशन अर्थवा वार्षिकी प्राप्त को हो, तो उस पर केवल प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।

2. “पेंशन” शब्द का अर्थ है पिछली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अर्थवा सेवाओं के कार्य निष्पादन के दौरान चोटप्रस्त होने के लिए प्रतिरूपि के रूप में की गई कोई आवधिक अदायगी।

3. “वार्षिकी” शब्द का अर्थ उस नियत राशि से है जो धन अर्थवा धन के मूल्य में पर्याप्त तथा पूरे प्रतिफल के लिए अदायगियाँ करने के किसी दायित्व के अधीन जीवन-पर्यन्त अर्थवा किसी विनिर्दिष्ट या निश्चित अवधि के दौरान नियत समय पर आवधिक रूप से देय हो।

4. पैरा 1 के उपबंधों के होते हुए भी, किसी सार्वजनिक योजना, जो किसी संविदाकारी राज्य अर्थवा उसके किसी राजनैतिक उप प्रभाग अर्थवा किसी स्थानीय प्राधिकरण की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा हो, के तहत प्रदत्त पेंशन और अदा किए गए अन्य भुक्तानों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

## अनुच्छेद-21

विद्यार्थियों और प्रशिक्षकों द्वारा प्राप्त अदायगियाँ

कोई विद्यार्थी अर्थवा व्यवसायिक प्रशिक्षा, जो किसी अन्य संविदाकारी राज्य की यात्रा करने के तुरंत पहले किसी

एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो केवल अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दसरे संविदाकारी राज्य में रह रहा है, उसे अपनी जीविका, शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे संविदाकारी राज्य के बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली अदायगियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

### अनुच्छेद - 22

प्राध्यापकों, अध्यापकों तथा शोध छात्रों द्वारा प्राप्त अदायगियां

1. कोई प्राध्यापक, अध्यापक अथवा कोई शोध छात्र जो किसी अन्य संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय, कालेज, स्कूल अथवा अन्य अनुमोदित संस्था में पढ़ाने अथवा शोध कार्य करने अथवा दोनों के प्रयोजनार्थ उस अन्य संविदाकारी राज्य की यात्रा करने के तुरत्त पहले किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था, उस पर उस अन्य संविदाकारी राज्य में उसके आगमन की तारीख से दो वर्षों की अवधि तक के लिए ऐसे प्राध्यापन अथवा शोध कार्य के निमित्त प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा।

2. यह अनुच्छेद अनुसंधान कार्य से प्राप्त आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होगा, यदि ऐसा अनुसंधान कार्य मूलतः किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी हित में किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 21 के प्रयोजनार्थ, किसी व्यष्टि को एक संविदाकारी राज्य का निवासी उस स्थिति में माना जाएगा यदि वह उस संविदाकारी राज्य का उस “वित्तीय वर्ष” में, जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य की यात्रा करता है, अथवा उसका तत्काल पूर्ववर्ती “वित्तीय वर्ष” में निवासी रहा हो।

4. पैरा 1 के प्रयोजनार्थ, “अनुमोदित संस्था” का आणथ उस संस्था से है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य के समुचित प्राधिकरण द्वारा किसी शैक्षिक अथवा अनुसंधान संस्था के रूप में अनुमोदित किया गया हो।

### अनुच्छेद—23

#### अन्य आय

1. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहने हुए, किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मदों पर, जहाँ-कहीं वे उत्पश्च होती हों, जिनपर इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विशेष रूप से विचार नहीं किया गया हो, केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में अथवा-परिभूति अचल सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय से भिन्न आय पर उस स्थिति में लागू नहीं होगी, यदि ऐसी आय

को प्राप्त करने वाला, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण किसी संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस संविदाकारी राज्य में व्यापार चलाता है अथवा उम्म दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पन्न करता है और वह अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में आय की अदायगी की जाती है वह आय ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावकारी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मदों पर, जिस पर इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

### अनुच्छेद—24

#### पूँजी

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा धारित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित, अनुच्छेद 6 में उल्लिखित अचल सम्पत्ति वाली पूँजी अथवा अचल सम्पत्ति के रूप में मान्य अधिकारों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

2. किसी कंपनी के पूँजी स्टाक के गेयरों वाली पूँजी, जिसकी सम्पत्ति में मुख्यतः प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति शामिल होती है, पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा। इस उपबंध के प्रयोजनार्थ, ऐसी कम्पनी के औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक प्रचालन से संबंधित अचल सम्पत्ति को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

3. किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार-सम्पत्ति का हिस्सा बनने वाली चल सम्पत्ति के रूप में निरूपित पूँजी जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में लगाई गई हो, अथवा किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध निश्चित स्थान से संबंधित चल सम्पत्ति को निरूपित करने वाली पूँजी पर स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पावन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

4. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में परिचालित पोतों तथा बायुयानों और ऐसे पोतों तथा बायुयानों के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति को निरूपित करने वाली पूँजी पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिस स्थान पर उस उद्यम की प्रभावी प्रबंध-व्यवस्था स्थापित है।

5. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूँजी के अन्य सभी हिस्सों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर सकेगा।

अनुच्छेद—25

### दोहरे कराधान का आयकरण

दोहरे कराधान का आयकरण निम्नानुसार किया जाएगा :

#### 1. भारत के मामले में :

(क) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है अथवा पूँजी का स्वामित्व रखता है, जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार फांस में कर लगाया जा सकता है, वहां भारत उस निवासी की आय पर उस रकम के बराबर कर से कटौती के रूप में चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा कटौती द्वारा छूट देगा जो फांस में अदा किए गए आयकर की रकम के बराबर होगी, और उस निवासी की पूँजी पर कर से कटौती के रूप में उतनी छूट प्राप्त होगी जो फांस में अदा किए गए पूँजीकर की रकम के बराबर होगा। तथापि, दोनों मामलों में भी किसी भी मामले में ऐसी कटौती (कटौती इ.) जने से पूर्व यथा-संगणित आयकर अथवा पूँजीकर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो उस आय या पूँजी, जैसा भी मामला हो, के कारण उनपर हुई मानी जा सकती हो, जिस पर फांस में कर लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जहां ऐसा निवासी कोई कम्पनी है, जिसके द्वारा भारत में अतिकर देय है, वहां फांस में अदा किए गए आयकर के बारे में कटौती पहले तो कम्पनी द्वारा भारत में देय आयकर में से की जाएगी और ऐसे के लिए, यदि कोई हो, भारत में उसके द्वारा देय अतिकर से कटौती की अनुमति दी जाएगी।

(घ) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अध्यधीन केवल फांस में कर लगाया जा सकता है, उस स्थिति में भारत इस आय को कर-आधार में शामिल करेगा लेकिन आयकर में से आयकर के उतने भाग की कटौती की अनुमति देगा जो फांस में उद्भूत हुई आय के कारण बनता हो।

#### 2. फांस के मामले में :

(क) भारत में उद्भूत होने वाली और इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार उस संविदाकारी राज्य में कराधेय लाभों तथा अन्य सशारात्मक आय को उस स्थिति में फेंच कर को संगणना के लिए हिसाब में लिया जाता है यदि ऐसी आय फांस के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई हो, ऐसी आय पर भारतीय कर की कटौती नहीं की जाएगी। उक्त लाभानुभोगी ऐसी आय पर लगने वाले फेंच कर के प्रति कर-फ्रेडिट का हकदार होगा। ऐसा कर-फ्रेडिट निम्नलिखित के बराबर होगा :

(i) अनुच्छेद 9 का पैराग्राफ 2, अनुच्छेद 11, 12, 13, अनुच्छेद 14 के पैरा 5, अनुच्छेद 16 के पैरा 3, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद

18 के पैरा 1 और 2 और अनुच्छेद 23 के पैरा 3 में उल्लिखित आय के मामले में उन अनुबंधों के उपबंधों के अनुसार भारत में प्रदत्त कर की रकम के बराबर। तथापि, यह रकम ऐसी आय पर लगने वाले फेंच कर की रकम से अधिक नहीं होगी।

(ii) प्रत्यं आय के मामले में, ऐसी आय पर लगने वाले फेंच कर की उस रकम के बराबर जो इस प्रकार छूट प्राप्त हो यह उपबंध अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 के पैरा 4 में उल्लिखित पारिधिक पर भी लागू होगा।

(ब) जहां तक अनुच्छेद 12 और 13 में उल्लिखित आय पर उप-पैरा (क) की प्रयोग्यता का प्रश्न है, यदि इन अनुबंधों के उपबंधों के अनुसार भारत में प्रदत्त कर की रकम पैरों आय पर लगने वाले फेंच कर की रकम से अधिक हो, तो ऐसी आय प्राप्त करने वाला फांस का निवासी अपने मामले का फांस के सम्बन्ध प्राधिकारी के समक्ष पेश कर सकता है। यदि प्रतीत हो कि ऐसी स्थिति के कारण कर लगेगा जो नियन्त आय पर कराधान में तुलनोदय नहीं है, तो सम्बन्ध प्राधिकारी भारत में प्रदत्त कर की फ्रेडिट न की गई रकम को उस निवासी द्वारा अंजित दिएगा स्नातों से अन्य आय पर उद्गृहीत फेंच कर में कटौती करने की अनुमति दे सकता है। इस उप-पैरे के उपबंध उस स्थिति में लागू, नहीं होगी यदि कर, उप पैरा (ग) और (घ) के उपबंधों के अनुसार भारत में प्रदत्त माना गया हो।

(ग) उप पैरा (क) (i) में उल्लिखित कर-फ्रेडिट के प्रयोगनार्थ “भारत में प्रदत्त कर” शब्दावली में किसी भी उस रकम को शामिल समझा जाएगा जो भारत के कानूनों के अध्यान और इस अभिसमय द्वारा उपबंधित सोसायटी के अंतर्गत भारतीय कर के रूप में किसी भी वर्ष के लिए संदेह हुआ होगा, यदि निम्नलिखित धाराओं, उपबंधों प्रादि के तहत उस वर्ष में कर-छूट अवश्य कर की कटौती मंजूर न की गई हो :

(i) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को धारा 10(4), 10(4ब्र.), 10(15)(iv) जिसके नहन व्याज का उल्लेख है, धारा 10(6)(vii) (क) जिसके तहत वेतन का उल्लेख है और धारा 803 जिसके तहत व्याज एवं लाभांश का उल्लेख है, जब तक ये धाराएँ प्रभूत रही थी, और इस अभिसमय पर दस्तावेज की तारीख से इनमें आशोधन नहीं किया गया है, अथवा मामली आशोधन किया गया है जिससे

कि उनके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव न पड़े : अथवा

- (ii) कोई भी अन्य उपबंध जो इस अभिसमय के लाने होते के बाद अधिनियमित होते हैं जिनके तहत कराधेश आय की संगणना करने समय उतनी कटौती अधिकारी करनी छूट अथवा कटौता की मंजूरी की गई हो जिसके संबंध में संविदाकारी राज्यों के सभस प्राधिकारी भारत के आर्थिक विकास के प्रयोजनार्थ समझौते हों, जिनमें कि उसमें इसके बाद कोई आशोकन नहीं किया गया है और अथवा केवल साखुली सा आशोकन किया गया हो जिसमें कि उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़े।
- (v) उप-पैरा (म) में उल्लिखित कर-क्रेडिट के प्रयोजनार्थ, जहाँ भारत में उद्भूत व्याज पर वास्तविक रूप से उद्गृहीत भारताय कर उस कर में कम हो जो भारत में अनुच्छेद 12 के पैरा 2 के उप-पैरा (क) और (ब) के अनुसार उद्गृहीत हो, तो ऐसे व्याज पर भारत में प्रदन कर की रकम को उक्त उपबंधों में उल्लिखित कर की दरों पर प्रदन किया हुआ माना जाएगा।
- तथापि, यदि भारतीय कानून के तहत उपरोक्त व्याज पर लागू सामान्य कर-दरों को पूर्वोक्त वाक्य में उल्लिखित दरों से कम कर दिया जाता है तो ये कमतर दरों उस वाक्य के प्रयोजनार्थ लागू होंगी।
- (६.) उप-पैरा (क) और (ग) के होते हुए भी किसी फांस-निवासी कम्पनी का किसी भारतीय निवासी कम्पनी द्वारा प्रदत्त लाभांशों पर केवल निगम कर से उस सीमा तक छूट प्राप्त होगी जितनी कि उन लाभांशों पर फांसीसी कानून के अनुसार उस स्थिति में छूट मिली होती यदि वे दोनों कम्पनियां फांस को ही निवासी रही होतीं।
- (च) फांस के वे निवासी जिनके पास भारत में कराधेश पूंजी है, उन पर ऐसी पूंजी पर फांस में भी कर लगेगा। फांसीसो कर की संगणना अनुच्छेद 24 के उपबंधों के अनुसार भारत में प्रदत्त कर की रकम के बराबर किसी कर-क्रेडिट की कटौती की अनुमति देते हुए की जाती है। तथापि, ऐसा क्रेडिट ऐसी पूंजी पर लगते वाले केवल कर ने अधिक नहीं होगा।

अनुच्छेद—26

सम-व्यवहार

- एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकां पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा किसी कराधान अथवा तत्संबंधों

ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं को जाएगी जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो दूसरे संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकां पर समान परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है। यद् उपबंध, अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी, ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।

2. अनुच्छेद 7 के पैरा प्राप्त जहाँ लागू होते हैं, उनको छोड़कर एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन पर लभाशा जाने वाला कर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस कर से अपेक्षाकृत कम अनुकूल नहीं होगा, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में समान कार्यकालांशों में लगे हुए उद्यमों पर लगाया जाता है।

3. पैरा प्राप्त 2 के उपबंधों का यह ग्रन्थ नहीं लभाया जाएगा कि दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई एक राज्य दूसरे राज्य के निवासियों को सिविल हैमिलन अथवा पारिवारिक उत्तरदायित्वों के लिए कराधान के प्रयोजनार्थ किसी भी प्रकार की वैसी व्यक्तिगत छूटें, गहरते और कटौतियों प्रदान करे जैसी वह अपने निवासियों को प्रदान करता है।

4. अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12 के पैरा 7 अथवा अनुच्छेद 13 के पैरा 8 के उपबंध जहाँ लागू होते हैं, उनको छोड़कर दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये गये ब्रात्र, रायलिट्यों और अन्य अदायगियां, ऐसे उद्यम के कर लगने योग्य लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के प्रधीन कटौती पाने योग्य होंगी जैसे कि वह प्रथमोन्लिखित संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई थी। इसी प्रकार दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दिया गया कोई भी क्रण, ऐसे उद्यम की कर लगने योग्य पूंजी के निर्धारण के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के प्रधीन कटौती पाने का पत्र होगा, जैसाकि वह प्रथमोन्लिखित संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अनुबंधित किया गया हो।

5. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्ण हो अवश्य अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हैं, प्रथमोन्लिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसा अपेक्षा लागू नहीं होगी, जो उस कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो, जो प्रथमोन्लिखित संविदाकारी राज्य के घैन्य उपरूप उद्यमों पर लागू है अथवा लागू हो सकती है।

भनुच्छेद — 27

## पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ किसी संविदाकारी राज्य का कोई निश्चयी मह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के परिणामस्वरूप उस पर कर लगा है अथवा लगा जा जाएगा जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुकूल नहीं है, तो वह उन संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों द्वारा उत्पन्न उपचारी उपायों के होते हुए भी, अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रख सकता है जिसका वह निवासी है। यह मामला उस कार्य की सूचना प्राप्ति की तारीख से तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके कारण इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप कर नहीं लगा है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उत्तित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिद्वारा की दूषित से, जो इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर महसूति द्वारा उस मामले को हल बरने का प्रयास करेगा। जो भी समझौता हुआ है उसको किसी तरह की समय-सीमाओं पर ध्यान न देने हुए संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों के तहत कार्यान्वयित किया जाएगा।

3. इस अभिसमय की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयां अथवा गंभीर उत्पन्न हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक महसूति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, जिनकी व्यवस्था इस अभिसमय में नहीं की गई है।

4. पूर्वोक्त पैग्राफ में व्यक्त अधिप्राय के लिए किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थी दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। यदि समझौते पर पहुंचने के लिए विचारों का मौखिक आदान-प्रदान उत्तित प्रतीत होता हो, तो ऐसा आदान-प्रदान किसी ग्राहीग के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हों।

5. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी संयुक्त रूप से अथवा घलग-घलग, यदि वे इसे जरूरी समझते हैं, इस अभिसमय को लागू करने के तरीके को और विशेष रूप से उन अपेक्षाओं को निर्धारित कर सकते हैं जिन्हें किसी संविदाकारी राज्य के निवासियों को पूरा करना पड़ेगा ताकि वे दूसरे संविदाकारी राज्य में इस अभिसमय के तहत उपवंधित कर-राहने अथवा छूटों को प्राप्त कर सकें।

भनुच्छेद — 28

## सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो इस अभिसमय के उपबंधों के अन्तर्गत आने वाले करों से संबंधित जहाँ तक उसके अन्तर्गत कराधान इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं हैं, विशेषतया इस अभिसमय के अथवा संविदाकारी राज्यों के प्रते ले कानूनों को कार्यान्वयित करने अथवा गतिस्वरूप अपवंचन को रोकने के लिए अथवा ऐसे करों की जातिसामाजी को रोकने के लिए अवश्यक है। किसी संविदाकारी राज्य से प्राप्त सूचना को उसी भाँति भी जिस भाँति से उस राज्य के स्वदेशी कानूनों के अन्तर्गत सूचना प्राप्त होती है, गोपनीय समझा जाएगा। तथापि, यदि सूचना का प्रेपण करने वाले राज्य में मूल रूप से गुप्त समझा जाता है तो उसे उस अभिसमय में समाविष्ट करों के निर्धारण, उनकी वसूली, उनका प्रबंधन अथवा उनके बारे में अभियोजन संबंधी कार्यवाई करने में अथवा उनसे संबंधित असीलों का निर्धारण करने में लगे हुए व्यक्तियों अथवा प्राधिकरणों (जिनमें न्यायालय तथा प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को ही प्रकट किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकरण ऐसे प्रयोगों के लिए ही सूचना का इन्तेमाल लारेंगे लेकिन वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकते हैं।

2. किसी भी स्थिति में पैग्राफ 1 के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा, जिसमें कि किसी संविदाकारी राज्य पर निम्ननिवित दायित्व डाला जाए :

(क) एक अक्ता दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है;

(ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना जो एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है;

(ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना जिसमें कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, ऑफोर्सिक, वाणिज्यिक अथवा व्यवसाय संबंधी गृप्त भेद अथवा ध्यानार्थक प्रक्रिया अथवा ऐसी सूचना प्रकट होती है, जिसको प्रकट करना सरकारी नीति के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद—29

## राजनयिक तथा कौशली कार्यकलाप

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा इस अभिसमय की पारियों के रीत हुए करार के उपबंधों

के अन्तर्गत इस अभिसमय के कारण राजनीतिक अथवा कौन्सिली अधिकारियों के विनीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुच्छेद—30

#### प्रवर्तन

1. प्रन्येक संविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य को इस अभिसमय को लागू करने के लिए उनकी अपनी विधि के अन्तर्गत "अपेक्षित" कार्यविधियों को पूरा किए जाने के बारे में अधिसूचित करेगा। यह अभिसमय इन अधिसूचनाओं के बाय जारी की गई अधिसूचनाओं की प्राप्ति की तारीख के पश्चात् दूसरे महीने की पहली तारीख से लागू होगा और इसका निम्नलिखित प्रभाव होगा:

#### (क) भारत में :

- (i) जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होगा उसके परवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन की अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में;
- (ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होगा उसके परवर्ती वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन को धारित पूँजी के संबंध में।

#### (ख) फ्रांस में :

- (i) जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होगा उसके परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले कैलेण्डर वर्ष के प्रथम दिन को धारित पूँजी के संबंध में;
- (ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होगा उसके परवर्ती कैलांडर वर्ष के किसी कैलेण्डर वर्ष के प्रथम दिन को धारित पूँजी के संबंध में।

2. आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए फ्रांस गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच जिस करार पर 26 मार्च, 1969 को पेरिस में हस्ताक्षर किए गए, वे वह समाप्त हो जाएगा और जैसे ही इस अभिसमय के तत्पर्यानी उपर्यंथ प्रभावी हो जाएंगे, उसके उपर्यों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।

### अनुच्छेद—31

#### समाप्ति

यह अभिसमय अनिश्चित काल तक लागू रहेगा। तथापि, दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस अभिसमय के लागू होने की तारीख से पांच घण्टों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी कैलेण्डर वर्ष के जून मास के 30वें दिन को अथवा उससे पहले राजनीतिक पाठ्यमांस से दूसरे संविदाकारी राज्य को इसकी समाप्ति

का लिखित रूप में नोटिस देंगेके और ऐसी स्थिति में, यह अभिसमय निम्नलिखित के लिए निष्प्रभावी हो जाएगा:

#### (क) भारत में :

- (i) जिस कैलेण्डर वर्ष में अभिसमय की समाप्ति के बारे में नोटिस दिया जाता है उसके परवर्ती वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में;
- (ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में अभिसमय की समाप्ति के लिए नोटिस दिया जाता है उसके परवर्ती वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन को धारित पूँजी के संबंध में।

#### (ख) फ्रांस में :

- (i) जिस कैलेण्डर वर्ष में अभिसमय की समाप्ति के बारे में नोटिस दिया जाता है उसके परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् शुरू होने वाले किसी कैलेण्डर वर्ष के अथवा किसी लेखा अवधि में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में;
- (ii) जिस कैलेण्डर वर्ष में अभिसमय की समाप्ति के बारे में नोटिस दिया जाता है उसके परवर्ती कैलेण्डर वर्ष के किसी कैलेण्डर वर्ष के प्रथम दिन को धारित पूँजी के संबंध में।

जिसके साथ में इसके लिए अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत् प्राधिक्रत अधीक्षताधरकर्ताओं ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये हैं।

सन् एक हजार नीसौ आनवे के नवे मास के उनतीमवें दिन को पेरिस में हिन्दी, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पत्र किया गया, जिसके तीनों पाठ समानतः प्रामाणिक हैं।

मनटेक सिंह आहनुवालिया

भारत राज्य की सरकार

की ओर से

हस्ता/-

फ्रांस गणराज्य की सरकार

की ओर से

#### प्रोतोकोल

आय और पूँजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिये फ्रांस और भारत के बीच अभिसमय पर हस्ताक्षर करने समय, अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित उपर्यों पर भर्ता रुए हैं जोकि इस अभिसमय के अभिन्न अंग होंगे:

- इस अभिसमय के प्रारम्भजार्थ, वह समझा जाता है कि जहां-जहां भी "राजनीतिक उप-प्रभाग" शब्द आयेंगे उनका तात्पर्य भारत के राजनीतिक उप-प्रभाग से होगा।

2. अनुच्छेद 7 (कारोबार संबंधी लाभ) के पैरा 1 के संबंध में, यह समझा जाता है कि यदि यूनाइटेड किंगडम और जर्मन संघ गणराज्य के साथ किये गए भागन के दो नये कर अभिसमयों, करारों अथवा प्रोतोकोलों में यह व्यवस्था है कि दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाने वाले किसी संविदा कारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उनके उन्हें अंश पर कर लगाया जा सकता है जो उस स्थायी संस्थापन के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में उद्भूत हुए हों अथवा जो : (क) उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से बेवे जाने वाले एक-समान अथवा उसमें भिनते जुनते किसम के माल अथवा पण्य वस्तुओं की उस दूसरे संविदाकारी राज्य में विक्री के कारण हुए हों; अथवा (ख) उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस अन्य राज्य में चलाये गए एक-समान अथवा उसमें मिलते-जुलते कारोबार संबंधी अन्य कार्यकलापों के कारण हुए हों, तो ऐसे उपबंध उसी सीमा तक लागू होंगे, जिस सीमा तक मौजूदा अभिसमय में व्यवस्था की गई है और ये भी उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जो भारा और यूनाइटेड किंगडम और जर्मन संघ गणराज्य के बीच निष्पत्त होने वाले उन दो अभिसमयों, करारों अथवा प्रोतोकोलों की बाद की तारीख होंगी। यह समझा जाता है कि इस मौजूदा अभिसमय पर केवल वे ही उपबंध लागू होंगे जो भारत और यूनाइटेड किंगडम एवं जर्मन संघ गणराज्य के बीच हुए दोनों नये अभिसमयों, करारों अथवा प्रोतोकोलों में शामिल हों।

3. अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 और 2 के संबंध में, जहाँ दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य का उद्यम दूसरे राज्य में वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन की मार्फत माल अथवा पण्य वस्तुओं की विक्री करता है अथवा व्यापार करता है, उस स्थिति में उस स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण उस उद्यम द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि के आधार पर नहीं किया जावेगा बल्कि उन लाभों का निर्धारण उस परिश्रमिक के आधार पर किया जायेगा जो स्थायी संस्थापन की ऐसी विक्री अथवा व्यापार में संबंधित वास्तविक कार्यकलापों के कारण उत्पन्न हुआ है। विशेषतः सर्वेक्षण, सञ्चार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्करों अथवा परिसरों की स्थापना अथवा निर्माण अथवा भार्यजनिक कार्यों के लिए ठेकों के मामते में, जब कि उद्यम का अपना स्थायी संस्थापन हो, ऐसे स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण ठेके की कुल राशि के अनुसार नहीं किया जाएगा बल्कि ठेके के उस भाग के आधार पर किया जाएगा, जिसे स्थायी संस्थापन द्वारा संविदाकारी राज्य में प्रभात्री रूप में सम्पन्न किया गया हो जिस राज्य में स्थायी संस्थापन स्थित है। ठेके के उस भाग में संबंधित लाभों, जिसे उद्यम के प्रधान कार्यालय द्वारा

कार्यान्वयित किया गया है, पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा, जिस राज्य का वह उद्यम निवारी है।

4. यह समझा जाता है कि अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 2 के संबंध में, विदेश व्यापार अथवा अण के संबंध में करारों को सम्पन्न किये जाने अथवा इस संबंध में भाव हस्ताक्षर किये जाने के कारणों से किसी स्थायी संस्थापन को लाभों का होना नहीं समझा जावेगा।

5. जिस संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन स्थित है, यदि उस राज्य के कानूनों के अनुपार अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (क) के उपबंधों के अनुरूप कार्यपालक और सामान्य प्रणालीनिक खर्चों पर प्रतिबंध लगाया जाता हो जिन्हें ऐसे स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण के लिये कटींती की अनुमति दी जा सकती, ऐसे मामते में यह समझा जाता है कि ऐसे स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने समय ऐसे कार्यपालक तथा सामान्य प्रणालीनिक खर्चों के संबंध में कटींती उस सीमा से कम नहीं होगी, जो उस अभिसमय पर हस्ताक्षर होने की तारीख को भागीदार प्रत्यक्षिय के अधिकार अधिनियम के अधिकार प्रत्यक्षिय है।

6. जहाँ ओत पर लगाये गये कर की राशि, अनुच्छेद 11, 12 अथवा 13 के उपबंधों के अध्यधीन प्रमाण्य कर की राशि में अधिक हो, उस स्थिति में कर की अनिरिक्त राशि की वापस अदायगी के लिये आवेदन-पत्र उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के पास, जिसमें इस कर को लगाया गया हो, करतावें जाने वाले कैलेंडर वर्ष की मासालि के पश्चात् तीरावां को अनुचित की भीतर प्रस्तुत कर दिया जाता चाहिए।

7. अनुच्छेद 11 (लासांग), 12(ब्याज) और 13 (ग्रलिट्यां, तकनीकी मेशांत्रों के लिये फीस और उपस्कर के इस्तेमाल के लिये अदायगियां) के संबंध में, यदि भारत और ओ.ई.सी.डी. की सदस्यता वाले किसी अन्य देश के बीच 1-9-1989 के बाद हस्ताक्षरित कोई अभिसमय करार, अथवा प्रोतोकोल के तहत, भारत अर्थाৎ कराधान की लाभांशों, ब्याज, रायलिट्यों, तकनीकी मेशांत्रों के लिये फीस अथवा उपस्कर के इस्तेमाल के लिये अदायगियों के संबंध में ओत पर किसी कम दर तक अथवा किसी ऐसी सीमा तक जो उस दर अथवा सीमा से अधिक मीठित हो अथवा जिसकी आय की उस मर्दों के संबंध में इस अभिसमय में व्यवस्था की गई है, तो आय की उस मर्दों के संबंध में उस अभिसमय, करार, अथवा प्रोतोकोल में यथा-उपबंधित वही दर अथवा सीमा इस अभिसमय के तहा तो लागू होगी और ये उस मर्दय तारीख से लागू होंगे जिस तारीख

से मौजूदा अधिसमय अथवा गंगत भारतीय अधिसमय करार अथवा प्रोतोकोल में से जो सबसे बाद में प्रवृत्त होगा।

8. यह समझा जाता है कि जो कर इस अधिसमय के विषय हैं अथवा जो उन करों के संबंध में लगाये गये किसी अर्थ-दण्ड को निरूपित करते हैं, उन करों के संबंध में हुई किसी चूक अथवा भूल के सिलसिले में सदैय किसी भी रकम को अनुच्छेद 12 (ब्याज) के प्रयोजनार्थ ब्याज नहीं समझा जाता है और उसे अनुच्छेद 25 (दोहरे कराधान का अपाकरण) के प्रयोजनार्थ नहीं समझा जाता है।

9. अनुच्छेद 13 (गणलिंगां, तकनीकी सेवाओं के लिये फीस एवं उपभक्त के इस्तेमाल के लिये अदायगियां) के संबंध में, इस अनुच्छेद के पैरा-2 के उपबन्धों के होते हुए भी, फ्रांस में उद्भूत तथा भारत के किसी निवासी को प्रदत्त रायलिंगों, तकनीकी सेवाओं के लिये फीस और उपभक्त के इस्तेमाल के लिये अदायगियों पर फ्रांस में कर नहीं लगेगा।

10. यह समझा जाता है कि यदि भारत ऐसी कोई लेबी लगाता है जो अनुच्छेद 2 में उल्लिखित नहीं है, जैसे अनुच्छेद 13 में उल्लिखित अदायगियों पर प्रतुसंधान तथा विकास उपकर और यदि भारत और ओ.ई.सी.डी. की सदस्यता वाले किसी अन्य देश के बीच किसी अधिसमय अथवा करार अथवा प्रोतोकोल के तहत इस अधिसमय के वृस्ताक्षर के बाद कोई लेबी लगाता है तो भारत को, पूर्णस्पैष अथवा आंशिक रूप से, लेबी की दर अथवा सीमा को कम करते हुए प्रत्यक्षतः अथवा पूर्णतः अथवा अशतः लेबी विषयक इस अधिसमय के अनुच्छेद 13 में यथा-उल्लिखित अदायगियों पर प्रश्नगत अधिसमय, करार अथवा प्रोतोकोल के तहत अनुमत भारतीय कर की दर अथवा सीमा को कम करते हुए अप्रत्यक्षतः ऐसी लेबी में राहत प्रदान करनी चाहिए, तरहनतर जिस तारीख से संगत भारतीय अधिसमय, करार अथवा प्रोतोकोल प्रवृत्त होता है उस तारीख से उस अधिसमय, करार अथवा प्रोतोकोल में यथा-उल्लिखित ऐसी राहतें इस अधिसमय के तहत भी लागू होंगी।

11. जहाँ तक अनुच्छेद 16 (पराश्रित व्यक्तिगत सेवायें) के संबंध में, यह समझा जाता है कि इस अनुच्छेद के उपबंध, दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी निवासी कंपनी के किसी उच्च स्तर की प्रबंधकीय हैमियत से किसी अधिकारी के रूप में उसकी अपनी हैमियत के अन्तर्गत किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक पर लागू होंगे। यह स्पष्ट है कि इस दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी में देय पारिश्रमिक के संबंध में अनुच्छेद 18 के पैरा 2 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

12. जहाँ तक अनुच्छेद 26 के पैरा 1 के लागू होने का सबध है, यह गमजा जाता है कि कोई व्यष्टि, विधिक

व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था जो किसी संविदाकारी राज्य के निवासी हों, को ऐसी ही परिस्थितियों में एक व्यष्टि, विधिक व्यक्ति, भागीदार अथवा संस्था नहीं माना जायेगा जो अन्य संविदाकारी राज्य का निवासी हो। यह उन मामलों में भी लागू होगा, जहाँ व्यष्टि, विधिक व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था, अनुच्छेद 3 (सामान्य परिभाषाएं) के पैराग्राफ 1. को लागू कर रहे हों, जिन्हें उस संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिक माना जायेगा, जिसके बे निवासी हों।

13. अनुच्छेद 25 (दोहरे कराधान का अपाकरण) के संबंध में, यह समझा जाता है कि उप-पैरा 2(क) (II) के प्रयोजनार्थ, वह प्राय जिसे भारत में पूर्णतः अथवा अंशतः छूट प्राप्त है, उसे भारत में करावेय आय के रूप में भी समझा जायेगा।

मन् एक हजार नौसौ व्यानवे के नवें मास के उन्नीसवें दिन को पैरिस में हिन्दी, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में निष्पत्ति किया गया, जिसके तीनों पाठ समाप्ति: प्रामाणिक हैं।

ह०/-

भारत गणराज्य की  
मरकार की ओर से

ह०/-

फ्रांस गणराज्य की  
मरकार की ओर से

MINISTRY OF FINANCE  
DEPARTMENT OF REVENUE  
(Foreign Tax Division)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 1994

(INCOME-TAX)

G.S.R. 681(E).—Whereas the annexed Convention between the Government of the Republic of India and the Government of the French Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital has come into force on the 1st day of August, 1994 on the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures required under their law for bringing into force of the said Convention in accordance with paragraph 1 of Article 30 of the said Convention;

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), section 24A of the Companies (Profits) Sur-tax Act, 1964 (7 of 1964) and 44A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

[F. No. 501/16/80 FTD]  
V.B. SRINIVASAN, Jr. Secy.

**ANNEXURE  
CONVENTION  
between**

the Government of the Republic of India  
and

the Government of the French Republic  
for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital.

The Government of the Republic of India and the Government of the French Republic,

desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital;

Have agreed as follow :

**Article 1  
PERSONAL SCOPE**

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

**Article 2  
TAXES COVERED**

1. The taxes to which this Convention shall apply are :

(a) in India

(i) the income-tax including any surcharge thereon;

(ii) the surtax; and

(iii) the wealth-tax,

(hereinafter referred to as "Indian tax")

(b) in France :

(i) the income-tax (*l'impôt sur le revenu*) including any withholding tax, pre-payment (*precompte*) or advance payment with respect thereto;

(ii) the corporation tax (*l'impôt sur les sociétés*) including any withholding tax, pre-payment (*precompte*) or advance payment with respect thereto; and

(iii) the wealth-tax (*l'impôt de solidarité sur la fortune*)

(hereinafter referred to as "French tax").

2. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Convention in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall

notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

**Article 3**

**GENERAL DEFINITIONS**

1. In this Convention, unless the context otherwise requires :

(a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and air space above it, as well as any other maritime zone in which India, according to the Indian law, has sovereign rights, other rights and jurisdictions in accordance with international law;

(b) the term "France" means the European and overseas departments of the French Republic including the territorial sea and the air space above it as well as the areas within which, in accordance with International law, the French Republic has sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting the natural resources of the sea-bed and its sub-soil and of the superjacent waters;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or France as the context requires;

(d) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

(e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative; and in the case of France, the Minister in charge of the Budget or his authorised representative;

(h) the term "national" means any individual possessing the nationality of a Contracting State and any legal person, partnership or association deriving its status from the laws in force in that Contracting State;

(i) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(j) the term "fiscal year" in relation to Indian tax means "previous year" as defined in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in relation to French Income-tax means calendar year;

(k) the term "tax" means Indian tax or French tax as the context requires.

2. As regard the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that Contracting State concerning the tax; to which the Convention applies.

#### Article 4

##### RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that Contracting State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :

- (a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interest cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person, other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

#### Article 5

##### PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purpose of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :

- (a) a place of management;
- (b) a branch
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, an oil, or gas well, at quarry or any other place of extraction of natural resources;
- (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
- (h) a premises used as a sales outlet;
- (i) an installation or structure used for the exploration of natural resources provided that the activities continue for more than 183 days.

3. A building site or construction, installation or assembly project constitutes a permanent establishment only where such site or project continues for a period of more than six months.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for other activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise;

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies is acting in one of the Contracting States on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State, if :

- (a) he has and habitually exercises in that Contracting State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless, his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or
- (b) he has no such authority, but habitually maintains in the first mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

6. An enterprise of one of the Contracting States shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other Contracting State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph if it is shown that the transactions between the agent and the enterprise were not made under at arm's length conditions.

7. The fact that a company which is a resident of one of the Contracting States controls or is controlled by a company, which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

## Article 6

### INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other

Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

## Article 7

### BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of one of the Contracting States shall be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid the profit of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of one of the Contracting States carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the determination thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, provided, however, that the

result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

3(a). In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the Contracting State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the taxation laws of that Contracting State. Provided that where the law of the Contracting State in which the permanent establishment is situated imposes a restriction on the amount of the executive and general administrative expenses which may be allowed, and that restriction is relaxed or overridden by any Convention, Agreement or Protocol signed after 1-1-1990 between that Contracting State and a third State which is a member of the OECD, the competent authority of that Contracting State shall notify the competent authority of the other Contracting State of the terms of the corresponding paragraph in the Convention, Agreement or Protocol with that third State immediately after the entry into force of that Convention, Agreement or Protocol and, if the competent authority of the other Contracting State so requests, the provisions of that paragraph shall apply under this Convention from that entry into force.

(b) However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purpose of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

#### Article 8

##### AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

3. For the purpose of this article, interest or funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such aircraft, and the provisions of article 12 shall not apply in relation to such interest.

4. The term "operation of aircraft" shall mean business of transportation by air of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft and any other activity directly connected with such transportation.

#### Article 9

##### SHIPPING

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, such profits may be taxed in the other Contracting State from which they are derived provided that the tax so charged shall not exceed :

- (a) during the first five fiscal years after the entry into force of this Convention, 50 per cent, and
- (d) during the subsequent five fiscal years, 25 per cent, of the tax otherwise imposed by the internal law of that Contracting State. Subsequently, only the provisions of paragraph 1 shall be applicable.

3. The provisions of paragraph 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a

joint business or an international operating agency engaged in the operation of ships.

4. For the purposes of this article interest arising on funds connected with the operation of ships in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships, and the provisions of article 12 shall not apply in relation to such interest.

## Article 10 ASSOCIATED ENTERPRISES

Where:

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other contracting State or  
 (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State and in other case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which wold, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises but by reason of those conditions have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

## Article 11 DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that Contracting State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. (a) A resident of India who receives dividends from a company which is a resident of France which, if received by a resident of France, would entitle such resident to a tax credit (avoir fiscal), shall be entitled from the French Treasury to a payment equal to such

tax credit (avoir fiscal) subject to the deduction of tax as provided for under paragraph 2 of this article.

(b) The provisions of sub-paragraph

(a) of this paragraph shall apply only to a resident of India who is  
 (i) an individual; or  
 (ii) a company which holds directly or indirectly less than 10 per cent of the capital of the French company paying the dividends.

(c) The provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph shall not apply if the recipient of the payment from the French Treasury provided for in sub-paragraph (a) of this paragraph is not subject to Indian tax in respect of the payment.

(d) Payments from the French Treasury provided for under sub-paragraph (a) of this paragraph shall be deemed to be dividend for the purpose of this Convention.

4. When the prepayment (precomp te) is levied in respect of dividends paid by a company which is a resident of France to a resident of India who is not entitled to the payment from the French Treasury referred to in paragraph 3 of this article with respect to such dividends, such resident shall be entitled to the refund of that prepayment, subject to the deduction of the withholding tax with respect to the refunded amount in accordance with paragraph 2 of this article.

5. As used in this article the term "dividends" means income from shares or other rights, not being debt-claims participating in profits, as well as income from other corporate rights treated in the same manner as income from shares by the taxation laws of the Contracting States of which the company making the distribution is a resident and any other item (other than interest which falls within the provisions of article 12) treated as a dividend or distribution under that law.

6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment of fixed base. In such case, the provisions of article 7, or article 15, as the case may be shall apply.

7. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company except in so far as such dividends are paid to a resident of that other Contracting State or in so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other Contracting State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other Contracting State :

### Article 12

#### INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed:

- (a) 10 per cent of the gross amount of the interest on loans made or guaranteed by a bank or other financial institution carrying on bona fide banking or financing business or by an enterprise which holds directly or indirectly at least 10 per cent of the capital of the company paying the interest ;
- (b) 15 per cent of the gross amount of the interest in all other cases.

3 Notwithstanding the provisions of paragraph 2:

(a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State provided it is derived and beneficially owned by:

- (i) the Government, a political sub-division or local authority of the other Contracting State; or
- (ii) the "Reserve Bank of India" in the case of India and the "Banque de France" in the case of France; or
- (iii) any other institution as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States;

(b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State if it is beneficially owned by a resident of the other Contracting State and is derived in connection with a loan or credit extended or endorsed by :

(i) in the case of France, the Banque Francaise du Commerce Exterieur, or the Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur (COFACE);

(ii) in the case of India, the Export-Import Bank of India;

(iii) any institution of the other Contracting State in charge of the public financing of external trade.

4. The term "interest" as used in this article means income from debt claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of article 7 or article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that Contracting State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply to the last mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of

each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

### Article 13

#### ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES AND PAYMENTS FOR THE USE OF EQUIPMENT

1. Royalties, fees for technical services and payments for the use of equipment arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. However, such royalties, fees and payments may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that Contracting State, but, if the recipient is the beneficial owner of these categories of income the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of such royalties, fees and payments.

3. The term "royalties" as used in this article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than payments to an employee of the person making the payments and to any individual for independent personal services mentioned in Article 15, in consideration for services of a managerial, technical or consultancy nature.

5. The term "payments for the use of equipment" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment.

6. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, fees for technical services or the payments for the use of equipment being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties, fees for the technical services or the payments for the use of equipment arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the royalties, fees for technical services or the payments for the use of equipment are effectively connected with such permanent establishment or fixed base.

In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

7. Royalties, fees or technical services or payments for the use of equipment shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that Contracting State. Where however the person paying the royalties, fees for technical services or the payments for the use of equipment, whether he is a resident of a Contracting State or not has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the contract under which the royalties, fees for technical services or the payments for the use of equipment are paid was concluded, and such royalties, fees for technical services or payments for the use of equipment are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties, fees for technical services or payments for the use of equipment shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, fees for technical services or the payments for the use of equipment, having regard to the royalties, technical services or the use of equipment for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provision of this Convention.

### Article 14

#### CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property, referred to in article 6, and situated in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other Contracting State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that Contracting State. For the purposes of this provision, immovable property pertaining to the industrial or commercial operation of such company shall not be taken into account.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 representing a participation of at least 10 per cent in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

6. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

#### Article 15

##### INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual or a partnership of individuals who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that Contracting State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State :

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other Contracting State; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "fiscal year"; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, surgeon, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

#### Article 16

##### DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of articles 17, 18, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other Contracting State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State if :

- (a) the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "fiscal year"; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other Contracting State; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other Contracting State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that Contracting State.

#### Article 17

##### DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in this capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

#### Article 18

##### INCOME EARNED BY ENTERTAINERS AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artiste or a musician or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, income derived by an entertainer or an athlete who is a resident of a contracting State from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State, if the activities in the other Contracting State are supported wholly or substantially from the public funds of the first-mentioned Contracting State, including any of its political sub-division or local authorities.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 and articles 7, 15 and 16, where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such in a Contracting State accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income shall be taxable only in the other Contracting State, if that other person is supported wholly or substantially from the public funds of that other Contracting State, including any of its political sub-divisions or local authorities.

#### Article 19

#### REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof or out of public funds of that Contracting State to an individual in respect of services rendered to that Contracting State or sub-division or authority shall be taxable only in that Contracting State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other Contracting State and the individual is a resident of that other Contracting State who is a national of that other Contracting State without being a national of the Contracting State to which the services are rendered.

2. Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that Contracting State or sub-division or authority shall be taxable only in that Contracting State.

3. The provisions of articles 16, 17 and 20 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or local authority thereof.

#### Article 20

#### NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension, other than a pension referred to in article 19, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions paid and other payments made under a public scheme which is a part of the social security system of a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof shall be taxable only in that Contracting State.

#### Article 21

#### PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND APPRENTICES

A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other Contracting State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other Contracting State on payments made to him by persons residing outside that other Contracting State for the purposes of his maintenance, education or training.

#### Article 22

#### PAYMENTS RECEIVED BY PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor, teacher, or a research scholar who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or research for

a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other Contracting State.

2. This article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this article and article 21, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that contracting State in the "fiscal year" in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "fiscal year".

4. For the purposes of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved as an educational or research institution by the appropriate authority of the concerned Contracting State.

#### Article 23

##### OTHER INCOME

1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing articles of this Convention, shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1, shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other Contracting State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of article 7 or article 15, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing articles of this Convention, and arising in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

#### Article 24

##### CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in article 6 or rights treated as immovable property, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other Contracting State.

2. Capital represented by shares of the capital stock of a company the property of which consists

directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that Contracting State. For the purposes of this provision, immovable property pertaining to the industrial or commercial operation of such company shall not be taken into account.

3. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services may be taxed in that other Contracting State.

4. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

5. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that Contracting State.

#### Article 25

##### ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Double taxation shall be avoided in the following manner :

###### 1. In the case of India :

(a) Where a resident of India derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in France, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in France, whether directly or by deduction; and as a deduction from the tax on the capital of that resident an amount equal to the capital tax paid in France. Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax (as computed before the deduction is given) which is attributable, at the case may be, to the income or the capital which may be taxed in France. Further, where such resident is a company by which surtax is payable in India, the deduction in respect of income tax paid in France shall be allowed in the first instance from income tax payable by the company in India and as to the balance, if any, from surtax payable by it in India.

(b) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, shall be taxable only in France, India may include this income in the tax base but shall allow as a deduction from the income tax that part of the income tax which is attributable to the income derived from France.

2. In the case of France:

(a) Profits and other positive income arising in India and which are taxable in that Contracting State in accordance with the provisions of this Convention, are taken into account for the computation of the French tax where such income is received by a resident of France. The Indian tax shall not be deductible from such income. The beneficiary shall be entitled to a tax credit against French tax attributable to such income. Such tax credit shall be equal :

(i) in the case of income referred to in Paragraph 2 or article 9, articles 11, 12, 13, paragraph 5 of article 14, paragraph 3 of article 16, article 17, paragraphs 1 and 2 of article 18, and paragraph 3 of article 23, to the amount of tax paid in India in accordance with the provisions of those articles. However, it shall not exceed the amount of French tax attributable to such income;

(ii) in the case of other income, to the amount of French tax attributable to such income, which is thus exempted. This provision shall apply also to remuneration referred to in article 19 and in paragraph 4 of article 20.

(b) As regards the application of sub-paragraph (i) to income referred to in articles 12 and 13 where the amount of tax paid in India in accordance with the provisions of these articles exceeds the amount of French tax attributable to such income, the resident of France receiving such income may present his case to the French competent authority. If it appears that such a situation results in taxation which is not comparable to taxation on net income, that competent authority may allow the non deducted amount of tax paid in India as deduction from the French tax levied on other income from foreign sources derived by that resident. The provisions of this sub-paragraph shall not apply where tax is deemed to be paid in India according to the provisions of sub-paragraphs (c) and (d).

(c) For the purposes of the tax credit referred to in sub-paragraph (a) (i) the term tax paid in

India" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Indian tax under the laws of India, and within the limits provided for by this Convention, for any year but for an exemption from or reduction of, tax granted for that year under :

- (i) Sections 10(4), 10(4B), 10(15)(iv) covering interest, section 10(6)(viia) covering salaries and section 80L covering interest and dividends, of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), so far as they were in force on, and have not been modified since, the date of the signature of this Convention, or have been modified only in minor respects so as not to affect their general character; or
- (ii) any other provisions which may be enacted after this Convention enters into force granting a deduction in computing the taxable income or an exemption or reduction from tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purposes of the economic development of India, if it has not been modified thereafter or has been modified only in minor respects so as not to affect its general character.
- (d) For the purposes of the tax credit referred to in sub-paragraph (c), where the Indian tax actually levied on interest arising in India is lower than the tax India may levy according to sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph 2 of Article 12, then the amount of tax paid in India on such interest shall be deemed to have been paid at the rates of tax mentioned in the said provisions.

However, if the general tax rates under Indian law applicable to the aforementioned interest are reduced below those mentioned in the foregoing sentence these lower rates shall apply for the purposes of that sentence.

- (e) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) and (c), dividends paid by a company which is a resident of India to a company which is a resident of France, shall be exempt from France Corporation tax to the extent that the dividends would have been exempt under French law if both companies had been residents of France.
- (f) Residents of France who own capital taxable in India may also be taxed in France on such capital. The French tax is computed by allowing a tax credit equal to the amount of tax paid in India in accordance with the provisions of article 24. However, such credit shall not exceed the French tax attributable to such capital.

## Article 26

## NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of one of the Contracting States shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the other Contracting State in the same circumstances are or may be subjected. The provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. Except where the provisions of paragraph 3 of article 7 apply the taxation on a permanent establishment which an enterprise of one of the Contracting States has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other Contracting State than the taxation levied on enterprises of that other Contracting State carrying on the same activities.

3. The provision of paragraph 3 shall not be construed as obliging one of the Contracting States to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

4. Except where the provisions of Article 10, paragraph 7 of Article 12 or paragraph 8 of Article 13, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of one of the Contracting States to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first mentioned Contracting State. Similarly, any debts of an enterprise of one of the Contracting States to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned Contracting State.

5. Enterprises of one of the Contracting States, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned Contracting State are or may be subjected.

## Article 27

## MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may notwithstanding the remedies provided by the national laws of those Contracting States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to avoidance of taxation not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting State.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

5. The competent authorities of the Contracting States may, jointly or separately, if they consider it necessary, settle the mode of application of the Convention and, especially the requirements to which the residents of Contracting State shall be subjected in order to obtain, in the other Contracting State, the tax reliefs or exemptions provided for by the Convention.

## Article 28

## EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of the Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention in so far as the taxation thereunder is not

contrary to the Convention, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Contracting State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

### Article 29

#### DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of agreement concluded between the parties to this Convention.

### Article 30

#### ENTRY INTO FORCE

1. Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedure required by its law for the bringing into force of this Convention. This convention shall enter into force on the first day of the second month following the date of reception of the later of these notifications and shall thereupon have effect :

(a) in India :

- (i) in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April

following the calendar year in which the Convention enters into force;

- (ii) in respect of capital which is held on the last day of any fiscal year beginning on or after the first day of April following the calendar year in which the Convention enters into force;

(b) in France :

- (i) in respect of income arising in any calendar year or accounting period beginning on or after the first of January following the calendar year in which the Convention enters into force;
- (ii) in respect of capital owned on the first day in any calendar year following the calendar year in which the Convention enters into force.

2. The Agreement between the Government of French Republic and the Government of the Republic of India for the avoidance of double taxation in respect of taxes on income signed in Paris on March 26, 1969 shall be terminated and its provisions shall cease to have effect when the corresponding provisions of this Convention shall become effective.

### Article 31

#### TERMINATION

1. This Convention shall remain in force indefinitely. However, either Contracting State may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to have effect:

(a) in India

- (i) in respect of income arising in any fiscal year beginning on or after the first day of April following the calendar year in which the notice of termination is given;

- (ii) in respect of capital which is held on the last day of any fiscal year beginning on or after the first day of April following the calendar year in which the notice of termination is given.

(b) in France

- (i) in respect of income arising in any calendar year or accounting period beginning on or after the first of January following the calendar year in which the notice of termination is given;

(ii) in respect of capital owned on the first day of any calendar year following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done in duplicate at Paris on this twenty-ninth day of September one thousand nine hundred and ninety two in the Hindi, French and English languages, all the texts being equally authentic.

**Dr. M.S. AHLUWALIA**      **Mr MICHEL TALY**  
For the Government of      For the Government of  
the Republic of India      the French Republic

#### PROTOCOL

At the time of proceeding to the signature of the Convention between France and India for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital, the undersigned have agreed on the following provisions which shall form an integral part of the Convention.

1. For the purposes of this Convention, it is understood that the words "political sub-division" wherever they occur shall mean political sub-division of India.

2. With respect to paragraph 1 of Article 7 (Business Profits), it is understood that if in both India's new tax Conventions, Agreements or Protocols, with the United Kingdom and Federal Republic of Germany, it is provided that the profits of an enterprise of a Contracting State carrying on business through a permanent establishment in the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State as are attributable directly or indirectly to that permanent establishment or attributable to: (a) Sales in that other Contracting State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (b) other business activities carried on in that other State, of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment, such provisions shall also apply to the extent so provided to the present Convention with respect from the date from which the later of those two Conventions, Agreements or Protocols between India and United Kingdom and the Federal Republic of Germany enters into force. It is understood that only the provisions included in both new Conventions, Agreements or Protocols between India and U.K. and F.R.G. shall apply to the present Convention.

3. In respect of paragraphs 1 and 2 of Article 7, where an enterprise of one of the Contracting States sells goods or merchandise or carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, the profits of that permanent establishment shall not be determined on the basis of the total amount received by the enterprise, but shall be determined only on the basis of the remuneration which is attributable to the actual activity of the permanent establishment for such sales or business. Especially, in the case of contracts for the survey, supply, installation or construction of industrial, commercial or scientific equipment or premises, or of public works, when the enterprise has a permanent establishment, the profits of such permanent establishment shall not be determined on the basis of the total amount of the contract, but shall be determined only on the basis of that part of the contract which is effectively carried out by the permanent establishment in the Contracting State where the permanent establishment is situated. The profits related to that part of the contract which is carried out by the head office of the enterprise shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise is a resident.

4. It is understood that with respect to paragraph 2 of Article 7, no profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the facilitation of the conclusion of foreign trade or loan agreements or the mere signing thereof.

5. Where the law of the Contracting State in which a permanent establishment is situated imposes in accordance with the provisions of sub-paragraph (a) of paragraph 3 of Article 7 a restriction on the amount of the executive and general administrative expenses which may be allowed as a deduction in determining the profits of such permanent establishment, it is understood that in determining the profits of such permanent establishment, the deduction in respect of such executive and general administrative expenses in no case shall be less than what is allowable under the Indian Income-tax Act as on the date of signature of this Convention.

6. Where tax has been levied at source in excess of the amount of tax chargeable under the provisions of Article 11, 12 or 13, applications for the refund of the excess amount of tax have to be lodged with the competent authority of the Contracting State having levied the tax, within a period of three years after the expiration of the calendar year in which the tax has been levied.

7. In respect of articles 11 (Dividends), 12 (Interest) and 13 (Royalties, fees for technical services and payments for the use of equipment), if

under any Convention, Agreement or protocol signed after 1-9-1989, between India and a third State which is a member of the OECD, India limits its taxation at source on dividends, interest, royalties, fees for technical services or payments for the use of equipment to a rate lower or a scope more restricted than the rate or scope provided for in this Convention on the said items of income, the same rate or scope as provided for in that Convention, Agreement or Protocol on the said items of income shall also apply under this Convention, with effect from the date on which the present Convention or the relevant Indian Convention, Agreement or Protocol enters into force, whichever enters into force later.

8. It is understood that any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes is not considered as an interest for the purposes of article 12 (interest) and is not considered as tax for the purpose of article 25 (Elimination of double taxation).

9. In respect of article 13 (Royalties, fees for technical services and payments for the use of equipment), notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, royalties, fees for technical services and payments for the use of equipment arising in France and paid to a resident of India, shall not be taxable in France.

10. It is understood that in case India applies a levy, not being a levy covered by Article 2, such as the Research and Development Cess on payments meant in Article 13, and if after the signature of this Convention under any Convention or Agreement or Protocol between India and third State which is a member of the OECD, India should give relief from such levy, directly by reducing the rate or the scope of the levy, either in full or in part, or indirectly by reducing the rate or the scope of the Indian tax allowed under the Convention, Agreement or Protocol in question on payments as meant

in Article 13 of this Convention with the levy, either in full or in part, then, as from the date on which the relevant Indian Convention, Agreement or Protocol enters into force, such relief as provided for in that Convention, Agreement or Protocol shall also apply under this Convention.

11. As regards article 16 (Dependent Personal Services), it is understood that the provisions of this article apply to remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as an official in a top level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State. It is clear that in respect of the remuneration due from a resident of this other Contracting State, the provisions of paragraph 2 of article 16 shall not apply.

12. As regards the application of paragraph 1 of Article 26, it is understood that an individual, legal person, partnership or association which is a resident of a Contracting State shall not be deemed to be in the same circumstances as an individual, legal person, partnership or association which is a resident of the other Contracting State. This shall also apply where such individuals, legal persons, partnership or association are, in applying paragraph 1.h of Article 3 (General Definitions), deemed to be nationals of the Contracting State of which they are residents.

13. In respect of article 25 (Elimination of Double Taxation), it is understood that for the purposes of sub-paragraph 2 (a) (ii), income which is exempt totally/partially in India shall also be considered as income taxable in India.

Done in duplicate at Paris——— on this 29th day of September———, one thousand nine hundred and ninety two, in Hindi, French and English languages, all the texts being equally authentic.

Sd/-

Sd/-

(DR. M.S. AHLUWALIA) (MR. MICHEL TALY)  
For the Government of For the Government of  
the Republic of India the French Republic

